



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2226]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939

No. 2226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2017

का. आ. 2532(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है और यह स्कीम केन्द्रीय सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा स्कीमों अर्थात् जनश्री बीमा स्कीम और आम आदमी बीमा स्कीम के विलयन संबंधी केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के साथ 1 जनवरी, 2013 से प्रवृत्त हुई थी, और विभाग द्वारा यथा अभिकल्पित “आम आदमी बीमा स्कीम हेतु नियम” के अनुसार क्रियान्वित की जाती है;

और, केन्द्रीय मंत्रालयी विभागों या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या किसी अन्य संस्थागत व्यवस्था या अन्य रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नोडल अभिकरण कहा गया है) नियमों के अनुसार स्कीम को प्रशासित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और उनसे भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह बीमा के अधीन बीमा कवरेज के प्रयोजन के लिए स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को पहचानने और नामांकित करने की अपेक्षा करती है;

और, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की दशा में नोडल अभिकरण से स्कीम को प्रशासित करने के लिए यथा नियुक्त राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है;

और, केन्द्रीय सरकार सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से बीमा के लिए समय-समय पर यथा विनिश्चित परिसीमन, यदि कोई हो, के साथ प्रीमियम के पचास प्रतिशत की सहायिकी देता है, और स्कीम नियमों के अनुसार आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) छात्रवृत्ति निधि के माध्यम से फायदाग्राहियों के बच्चों को भी छात्रवृत्तियां देती है;

और, स्कीम के अधीन प्रीमियम में सब्सिडी और छात्रवृत्तियों के भुगतान में सहायिकी (दोनों को मिलाकर इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्गस्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: —

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे किसी व्यक्ति को, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उनसे यह अपेक्षा है कि वे 31 जुलाई, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करें परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंध के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार इस मंत्रालय से अपनी नोडल अभिकरण के माध्यम से अपेक्षित है कि वह अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं करा चुके फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे तथा संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने के मामले में वह मंत्रालय अपनी नोडल अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के वर्तमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परन्तु ऐसे व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने तक, स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदे दिए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा दिया हो, तो उसकी आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या
(ii) नीचे दिए गए पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो वाली डाकघर पासबुक की बैंक पासबुक; या (ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या (iv) राशन-कार्ड; या (v) सरकारी कर्मचारी आईडी कार्ड; या (vi) मतदाता पहचान पत्र; या

(vii) मनरेगा कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (x) सरकारी पत्र-शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो सहित पहचान का प्रमाण-पत्र, या (xi) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी;

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के उद्देश्य से यह मंत्रालय अपनी नोडल अभिकरण के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्:—

- (1) मीडिया तथा व्यक्ति सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में अवगत कराया जा सके और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर 31 जुलाई, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जाए तथा उन्हें स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।
 - (2) यदि फायदाग्राहियों आस-पास के क्षेत्रों अर्थात् ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन न करवा सके हों तो यह मंत्रालय अपनी नोडल अभिकरण के माध्यम से सुलभ स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही मंत्रालय के नामनिर्दिष्ट कार्मिक अथवा नोडल अभिकरण के पास आधार के लिए नामांकन हेतु अपना नाम, पता, मोबाइल संख्या तथा पैरा (1) के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए अथवा इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध नामांकन करा सकते हैं।
3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एम-21015/02/2017-आरडब्ल्यू]

रजीत पुनहानी, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/ संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2017

S.O. 2532(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment in the Government of India is administering the Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) (hereinafter referred to as the Scheme) and the

scheme came into force from 1st January 2013 with the decision of Union Cabinet on merging of two Central Government Social Security Schemes, namely, Janashri Bima Yojana and Aam Aadmi Bima Yojana, and is implemented as per the “Rules for Aam Aadmi Bima Yojana” as designed by the Department;

And whereas, the Central Ministerial Departments or State Governments or Union Territory Administrations or any other institutionalised arrangement or any registered Non-Government Organisation, are appointed to administer the Scheme (hereinafter referred to as the Nodal Agencies) as per the rules, and they are expected to identify and enroll the beneficiaries under the Scheme for the purpose of insurance coverage under the group insurance of Life Insurance Corporation of India.

And whereas, the nodal agency in case of rural landless households shall mean the State Government or Union territory Administration as appointed to administer the Scheme;

And whereas, the Central Government subsidizes fifty per cent of the premium, with limitations, if any, as decided from time to time, for the insurance through Social Security Fund, and also pays scholarships to the children of the beneficiaries as per the Scheme rules through Aam Aadmi Bima Yojana (AABY) Scholarship Fund;

And whereas, the subsidy in premium and payment of scholarships (together hereinafter referred to as the benefits) under the Scheme involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) An individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31st July, 2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provision of section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the Ministry through its Nodal Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Nodal Agencies shall facilitate Aadhaar enrolment at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

- a. (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

- b. (i) Bank Passbook of Post Office Passbook with Photo; (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employees Government ID Card; or (vi) Voter Identity Card; or (vii) MGNREGS card; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (xi) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme, the Ministry through its Nodal Agencies shall make all required arrangements including the following, namely:—

- (1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st July, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
- (2) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrollment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Nodal Agencies shall provide Aadhaar enrollment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated official of the Ministry or the Nodal Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir

[F. No. M-21015/02/2017-RW]

RAJIT PUNHANI, Director-General (Labour Welfare)/Jt. Secy.